के लिए और जो विदेश से गेहूं आने वाला है, इसकी कीमत, क्योंकि वह पंजाब से आने वाला नहीं है, वह डायरेक्ट शिप से आएगा चैन्नई में या विशाखापट्टनम में या मुम्बई में या कांडला में या कारवार में और जो आएगा, उसको पूरे साल हम रखने वाले नहीं हैं। उसके आने के बाद इमिडिएटली उसका डिस्ट्रिब्यूशन हम करेंगे, उसी एरिया में, जिससे गोदाम चार्जिस, इंटरेस्ट, स्टोरिंग चार्जिज़ का बोझ सरकार के ऊपर नहीं आएगा। और इसलिए डोमेस्टिक व्हीट, जिसकी कीमत हमें यहां पर पर्चेज़ करके राज्यों में भेजने के बाद 1120/- रुपये प्रति क्विंटल पड़ती है या 11,200/- रुपये प्रति टन पड़ती है, लेकिन जो गेहूं सरकार ने बाहर से पर्चेज़ किया है, उसकी कीमत उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचने तक 997/- रुपये प्रति क्विंटल, अर्थात् 9,978/- रुपये प्रति टन पड़ेगी। हमने जो पहले पांच लाख टन के पर्चेज़िज़ किए, हमारी बचत उनसे 399 करोड़ रुपये होगी। यहां पर मैं सेविंग की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब मुझे उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित करना है, तब मुझे यह भी देखना होगा कि उसकी कीमत इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि बिल सब्सिडी से ज्यादा आ जाए, आप इस बात को नहीं भूल सकते। सदन के सामने मुझे यह बताते हुए खुशी है कि पिछले ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : अगर आप पांच मिनट के लिए यील्ड करते हैं तो Shri Mani Shankar Aiyar has to make a Statement because he has to go.

STATEMENTS BY MINISTERS

Status of implementation of recommendtions contained in the Fourth Report of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Rural Development

and

Status of implmentation of recommendations contained in the Twelfth Report of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Rural Development

THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): Sir, I lay a copy of each of the statements.

SHORT DURATION DISCUSSION

Import of wheat and agrarian distress - *Contd.*

श्री शरद पवार : इसलिए जो गेहूं बाहर से आया है, कंज्यूमर को उसकी जो अल्टीमेट कीमत पड़ने वाली है, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत को भेजने के बाद जो टोटल कॉस्ट आएगी, यह पहले वाली कॉस्ट से कम है और इससे 399 करोड़ रुपये की बचत होने वाली है।